5

प्रणब मुखर्जीः भारतीय राजनीति के कुशल शिल्पी

6

एथनाल पेट्रोल ने चीनी का बढ़ाया संकट

7

सड़क पर उठे सवाल कैसे बदल देते हैं सत्ता

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 15 प्रति सोमवार, 31 अगस्त 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

लोहा चोर ट्रांसपोर्ट कारोबारी इंद्रजीत सिंह 'छोटू' के ठिकानों पर GST की दबिश

रिकॉर्ड की जांच से उठेगा अवैध कारोबार से पर्दा, लोहा चोरी के बाद टैक्स चोरी से भी लगाया जा रहा सरकार को चूना

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित लोहा चोर ट्रांसपोर्ट कारोबारी इंद्रजीत सिंह 'छोटू' अभी तक तो भिलाई स्टील प्लांट में लोहा चोरी के नाम पर बदनाम हैं लेकिन अब वह टैक्स चोरी के शिकंजे में भी आ गये हैं। बताया जा रहा है कि इंद्रजीत सिंह ने करोड़ों की टैक्स चोरी करके शासन को चूना लगाया है। हाल ही में लोहा चोर इंद्रजीत सिंह उर्फ 'छोटू' से जुड़े ठिकानों पर स्टेट GST विभाग की कार्रवाई ने कारोबारी और ट्रांसपोर्ट जगत में हलचल पैदा कर दी है। स्टेट GST दुर्ग की टीम ने हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी (HTC) के हथखोज स्थित कार्यालय और गोदाम के साथ-साथ बलौदाबाजार स्थित कंपनी के यार्ड में भी पहुंचकर कारोबारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की। कई घंटे तक चली इस कार्रवाई में अधिकारियों ने कंपनी के विभिन्न रिकॉर्ड, कागजात और कारोबारी गतिविधियों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की। हालांकि, इस कार्रवाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि GST विभाग ने अब तक आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया है कि जांच किस विशेष शिकायत, सूचना या कथित कर अनियमितता के आधार पर की गई। अलग-अलग स्थानों पर जांच किए जाने से यह संकेत मिलता है कि विभाग कंपनी की कारोबारी गतिविधियों और उनके दस्तावेजी रिकॉर्ड का व्यापक स्तर पर मिलान करना चाहता है। वाहनों के संचालन और माल परिवहन से संबंधित रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में होने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही रिकार्ड की जांच पड़ताल के बाद इंद्रजीत सिंह के अवैध कारोबार से पर्दा हटेगा।

करीब 1,500 ट्रकों से जुड़ा कारोबार

इंद्रजीत सिंह उर्फ 'छोटू' को भिलाई के प्रमुख ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में गिना जाता है। वे हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर हैं और कंपनी करीब 1,500 ट्रकों के संचालन से जुड़ी बताई जाती है। (शेष पेज 2 पर)

उद्योगपतियों ने किया छत्तीसगढ़ के जंगलों का विनाश

विकास और पर्यावरण के बीच संघर्ष में पिस रहे आदिवासी

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ भारत के उन राज्यों में से एक है, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। राज्य का लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है और यहाँ घने साल, सागौन तथा मिश्रित वन पाए जाते हैं। बस्तर, सरगुजा, कोरबा, कांकेर, जशपुर और रायगढ़ जैसे क्षेत्र अपनी जैव विविधता तथा आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। इन जंगलों ने सदियों से लाखों आदिवासियों को भोजन, जल, औषधि और आजीविका प्रदान की है। किंतु पिछले कुछ दशकों में औद्योगिकीकरण, खनन परियोजनाओं तथा बड़े उद्योगों के विस्तार ने इन जंगलों पर गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है। वनमंत्री केदार कश्यप और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन छत्तीसगढ़ की पहचान मिटाने पर तुले हुए हैं। भविष्य की चिंताओं को दरकिनार कर उद्योगपतियों को जंगल के जंगल समर्पित कर रहे हैं। आदिवासियों के विरोध के बावजूद उदयोगपतियों को हसदेव जंगल दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पर्यावरणीय अनुमति से खनन तक में मंत्रियों को भारी भरकम लाभ दिया जाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में खनिज के उत्खननों की अनुमतियां फटाफट दी जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ को देश की "खनिज राजधानी" भी कहा जाता है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे खनिजों के विशाल भंडार हैं। इन संसाधनों के दोहन के लिए अनेक औद्योगिक घरानों तथा खनन कंपनियों को खदानों और परियोजनाओं की अनुमति दी गई। परिणामस्वरूप हजारों हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण हुआ और अनेक क्षेत्रों में जंगलों की कटाई तेज हो गई। (शेष पेज 3 पर)

साय सरकार के प्रयासों से औद्योगिक विकास की नई राह पर छत्तीसगढ़

राजधानी से रोजगारधानी की ओर बढ़ता नवा रायपुर अटल नगर

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास यात्रा अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच रही है, जहां निवेश केवल पूंजी का आगमन नहीं, बल्कि रोजगार, कौशल, तकनीक और आर्थिक अवसरों के विस्तार का माध्यम बन रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को नई गति देने के साथ नवा रायपुर अटल नगर को आधुनिक प्रशासनिक राजधानी से आगे बढ़ाकर निवेश और रोजगार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नवा रायपुर की सुनियोजित अधोसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और भविष्य की तकनीक आधारित उद्योगों के लिए तैयार किए जा रहे इकोसिस्टम ने प्रदेश में निवेश की नई संभावनाओं को आकार दिया है। सरकार का जोर ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने पर है, जो प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित कर सकें और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को विनिर्माण एवं तकनीक आधारित नई दिशा दे सकें। (शेष पेज 3 पर)

पेट्रोलियम क्षेत्र की नई दिशा तय करने वाली स्थाई समिति का हिस्सा रहे कमलनाथ की ऊर्जा क्षेत्र में बदलावों की नींव वाले दौर में संसदीय कमेटी में रही महत्वपूर्ण भूमिका

-विजया पाठक

देश के पेट्रोलियम क्षेत्र में आज जब आपूर्ति, कीमतों और उपलब्धता को लेकर नई चुनौतियां सामने आती हैं, तब पुराने संसदीय अनुभवों और नीतिगत समीक्षा से सीख लेना समय की जरूरत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ नेता कमलनाथ 1998-99 में पेट्रोलियम एवं रसायन संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे। उस समय समिति में अध्यक्ष सहित कुल 23 सदस्य थे और समिति की अध्यक्षता डॉ. बलराम जाखड़ कर रहे थे। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक उपक्रमों तथा नीतिगत विषयों की संसदीय समीक्षा की गई थी। इसलिए कमलनाथ ने पेट्रोलियम क्षेत्र में उस दौर में जो सिफारिश दी उन्हें सरकार ने स्वीकार किया। (शेष पेज 2 पर)

पेट्रोलियम क्षेत्र की नई दिशा तय करने वाली स्थाई समिति का हिस्सा रहे कमलनाथ

(पेज 1 का शेष)

यही कारण है कि कमलनाथ की भागीदारी को देश के ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों की संसदीय निगरानी के उनके अनुभव के रूप में अवश्य देखा जा सकता है। उस दौर में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां देश की ऊर्जा व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला थी। आज केंद्र सरकार के सामने पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रश्न हैं। ऐसे समय में राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर देश के अनुभवी नेताओं, नीति विशेषज्ञों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के अनुभव का उपयोग किया जाना चाहिए। कमलनाथ का लंबा संसदीय अनुभव उन्हें ऐसे विमर्श में उपयोगी आवाज बना सकता है। वर्तमान सरकार यदि पुराने अनुभवों और नए नीतिगत उपायों के बीच समन्वय स्थापित करे, तो पेट्रोलियम क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक और व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है।

भारत के पेट्रोलियम और रसायन क्षेत्र के विकास की कहानी केवल हाल के वर्षों की नहीं है। उदारीकरण के बाद 1990 के दशक में देश की ऊर्जा जरूरतों, घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन, निजी निवेश, रिफाइनिंग क्षमता, पेट्रो केमिकल उद्योग और उभरती ऊर्जा तकनीकों को लेकर कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों की नींव रखी गई। 1998-99 में भारत का पेट्रोलियम क्षेत्र एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों पर निर्भर था, वहीं दूसरी ओर आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी भागीदारी और प्रतिस्पर्धा के लिए रास्ते खोले जा रहे थे।

संसदीय निगरानी का महत्वपूर्ण दौर

पेट्रोलियम एवं रसायन संबंधी स्थायी समिति का मूल काम सरकार के मंत्रालयों की योजनाओं, बजट और नीतियों की संसदीय समीक्षा करना था। समिति ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदान मांगों की जांच की। समिति ने

मंत्रालय के अधिकारियों से साक्ष्य लिए और इसके बाद रिपोर्ट को अपनाया। कमलनाथ की भूमिका इसी संसदीय प्रक्रिया के भीतर थी। उस समय के किसी विशिष्ट सरकारी निर्णय को अकेले कमलनाथ का निर्णय बताने के बजाय यह कहना अधिक तथ्यात्मक है कि वे उस संसदीय समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा थे, जिसमें पेट्रोलियम क्षेत्र की भविष्य की दिशा पर महत्वपूर्ण विमर्श हुआ।

घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की चुनौती

समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में एक घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन को बढ़ाना था। रिपोर्ट में कहा गया कि देश के हाइड्रोकार्बन भंडार सीमित थे और नई खोजों में तेजी नहीं आने पर आने वाले वर्षों में आयात पर निर्भरता बढ़ सकती थी। समिति ने इस स्थिति की गंभीरता को रेखांकित किया और मंत्रालय द्वारा खोज गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। रिपोर्ट में 3-डी सिस्मिक सर्वे, गहरे पानी और नए फ्रंटियर बेसिन में खोज, आधुनिक तकनीक, अतिरिक्त खोजी कुओं तथा निजी भागीदारी जैसे उपायों का उल्लेख है। उस समय देश के लगभग 45 प्रतिशत तलछटी बेसिन पूरी तरह अन्वेषित नहीं थे। इस स्थिति ने भारत के लिए नए तेल और गैस संसाधनों की खोज को रणनीतिक आवश्यकता बना दिया था। यह वह दौर था जब ऊर्जा सुरक्षा को लेकर संसदीय विमर्श अधिक व्यापक हो रहा था। कमलनाथ जैसे अनुभवी सांसद का इस समिति में होना उस संसदीय निगरानी व्यवस्था का हिस्सा था, जिसमें सरकार की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल-जवाब तथा समीक्षा की जाती थी।

रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर

भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र में केवल तेल की खोज ही पर्याप्त नहीं थी। देश में बढ़ती खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनिंग क्षमता का विस्तार भी आवश्यक था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार उस समय देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 67.55 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी। विभिन्न नई रिफाइनरियों और विस्तार परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इसे 2001-02 तक लगभग 113.95 मिलियन मीट्रिक टन और 2006-07 तक लगभग 145.75 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचाने की योजना थी। रिफाइनिंग क्षमता का यह विस्तार बाद के वर्षों में भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण आधार बना। देश में सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों के साथ निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का विस्तार भी इसी व्यापक बदलाव का हिस्सा था।

रसायन और उर्वरक क्षेत्र की भी समीक्षा

कमलनाथ की समिति की जिम्मेदारी केवल पेट्रोलियम तक सीमित नहीं थी। समिति के अधिकार क्षेत्र में रसायन एवं उर्वरक विभाग भी शामिल था। समिति ने उर्वरक विभाग की अनुदान मांगों की भी जांच की और इस विषय पर अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में समिति ने सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की। इसी अवधि में देश में दवा और रसायन उद्योग को लेकर भी नीतिगत पुनर्विचार चल रहा था। उस दौर की समीक्षा के आधार पर वर्तमान सरकार को भी अमल करना चाहिए। जिससे काफी हद तक पेट्रो पदार्थों की समस्या से उबरा जा सकता है। राजनीतिक वैमनस्यता से हटकर देशहित ही सर्वोपरि होना आवश्यक है।

लोहा चोर ट्रांसपोर्ट कारोबारी इंद्रजीत सिंह 'छोटू' के ठिकानों पर GST की दबिश

(पेज 1 का शेष)

इतना बड़ा परिवहन नेटवर्क होने के कारण कंपनी की कारोबारी गतिविधियां केवल एक स्थान तक सीमित नहीं हैं। यही वजह है कि GST टीम ने भिलाई के साथ बलौदाबाजार स्थित यार्ड को भी जांच के दायरे में रखा। इतने बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में रोजाना बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही, माल की ढुलाई, बिलिंग और भुगतान जैसी गतिविधियां होती हैं। ऐसे में कर संबंधी रिकॉर्ड का सही और व्यवस्थित होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। GST विभाग की जांच में इन्हीं पहलुओं से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल किए जाने की बात सामने आई है।

भिलाई स्टील प्लांट यानी BSP से भी जुड़ा है कारोबार

HTC के कारोबार का एक हिस्सा भिलाई स्टील प्लांट यानी BSP से भी जुड़ा बताया जाता है। कंपनी की करीब 60 से 70 गाड़ियां BSP में परिवहन संबंधी कामों में लगी हैं। इन वाहनों का इस्तेमाल प्लांट परिसर में लोडिंग और परिवहन से जुड़े कार्यों में किए जाने की बात कही गई है। ऐसे में कंपनी के परिवहन कारोबार से जुड़े बिल, भुगतान, वाहन संचालन और अन्य रिकॉर्ड GST जांच में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मौजूदा जांच में BSP से जुड़े कारोबार को लेकर विभाग ने कोई विशेष आपत्ति दर्ज की है। इस संबंध में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

चोरी करने का अनूठा तरीका

डीजल टैंक में एक भाग में पानी और एक भाग

में डीजल और ट्रकों के बेस में खाचे बनवाकर छाई मतलब लोहे की डस्ट भरकर प्लांट में ले जाना, काँटा करवाकर भिलाई स्टील प्लांट अंदर जाना और अंदर टैंक का पानी और डस्ट को खाली करके प्लांट से लोहा चोरी करवाता है। इंद्रजीत ने भिलाई स्टील प्लांट से लोहा चोरी करने का नायाब तरीका अपनाया। डीजल टैंक का आधा हिस्सा पानी से भरा होता है। उसी पानी को अंदर प्लांट में खाली किया जाता है। चेम्बर्स में छाई भर कर प्लांट में ले जाते हैं। काँटा कराकर अंदर फिर छाई और पानी खाली किया जाता है। उसके बदले चोरी किया हुआ लोहा भर लिया जाता है।

इंद्रजीत सिंह की सामाजिक पहचान भी चर्चा में

इंद्रजीत सिंह उर्फ 'छोटू' केवल ट्रांसपोर्ट कारोबार तक सीमित नहीं हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार वे विभिन्न सामाजिक और खेल संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें SBS हॉस्पिटल भिलाई के डायरेक्टर के रूप में भी बताया गया है। इसके अलावा वे भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, यूथ सिख सेवा समिति भिलाई, सर्व समाज कल्याण समिति और न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ जैसी संस्थाओं में जिम्मेदारियां संभालते बताए जाते हैं। इसी वजह से GST की कार्रवाई ने कारोबारी हलकों के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर भी ध्यान खींचा है। हालांकि कार्रवाई को उनके सामाजिक या अन्य दायित्वों से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा जांच का केंद्र कंपनी के कारोबारी रिकॉर्ड और GST संबंधी दस्तावेज हैं।

बीजेपी नेता ने साफ कर दिया करोड़ों का लोहा

मामला दुर्ग का है, जहां प्लांट से कचरा साफ करने के नाम पर करोड़ों का कीमती लोहा ही 'साफ' कर दिया गया। इस 'चमत्कारी' खेल के मास्टरमाइंड निकले भाजपा के वैशाली नगर मंडल कोषाध्यक्ष भास्कर मुदलियार। जैसे ही पुलिस ने उन्हें 250 टन लोहे के साथ धर दबोचा, भाजपा ने 06 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्लांट के जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जीएम के साथ मिलकर 'कचरे के नीचे करोड़ों का माल' दबा रहे थे। पुलिस ने 3.22 करोड़ की गाड़ियां और क्रेन जब्त कर ली हैं। अब देखना यह है कि जेल की सलाखों के पीछे इन 'लौह-प्रेमियों' को कितना जंग लगता है।

छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में पिछले 40 वर्षों से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लोहे की चोरी होने का दावा किया गया है। इस मामले ने तब बड़ा रूप ले लिया जब दुर्ग पुलिस ने भिलाई में बड़े पैमाने पर हो रहे एक संगठित लोहा चोरी रैकेट का पर्दाफाश किया। पिता के मरने के बाद बेटा इन्द्रजीत सिंह इस काम को अंजाम दे रहा है। भिलाई स्टील प्लांट में सीआईएसएफ और पुलिस की मदद से लोहा चोरी का साम्राज्य खड़ा कर लिया।

साय सरकार के प्रयासों से औद्योगिक विकास की नई राह पर छत्तीसगढ़

(पेज 1 का शेष)

औद्योगिक विकास के साथ रोजगार सृजन पर जोर

साय सरकार की औद्योगिक नीति का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि निवेश को केवल उद्योग स्थापना तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि उसे रोजगार सृजन से जोड़ा जा रहा है। टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सेमीकंडक्टर और एमएसएमईजैसे क्षेत्रों में विकसित हो रही परियोजनाएं इस सोच को स्पष्ट करती हैं। नवा रायपुर में विकसित किया जा रहा टेक्सटाइल पार्क इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। लेयर-2 के ग्राम कुरूं में इसके लिए 100 एकड़ भूमि CSIDC को आवंटित की गई है। यहां टेक्सटाइल विनिर्माण से जुड़ी गतिविधियों को विस्तार देने की तैयारी है। स्विफ्ट टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 235 करोड़ रुपए के निवेश से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत इसी औद्योगिक वातावरण का परिणाम है। इस इकाई से लगभग 4,650 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसी क्रम में पुनीत क्रिएशन के साथ 175 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से टेक्सटाइल पार्क में लगभग 10 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने का लक्ष्य है। यह पहल विशेष रूप से स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने की क्षमता रखती है।

फार्मा क्षेत्र में निवेश से स्वास्थ्य उद्योग को मिलेगी गति

साय सरकार ने औद्योगिक विविधीकरण के तहत फार्मास्युटिकल क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नवा रायपुर के सेक्टर-22 में 132 एकड़ भूमि CSIDC को आवंटित कर फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। फार्मा पार्क में करीब 2 हजार करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 1,400 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। टोरेंट फार्मा, एविला फार्मास्युटिकल्स और विटालिस हेल्थ जैसी कंपनियों के साथ 735 करोड़ रुपए के एमओयू इस दिशा में आगे बढ़ते कदमों को दर्शाते हैं। फार्मा पार्क का लाभ केवल प्रत्यक्ष रोजगार तक सीमित नहीं रहेगा। दवा निर्माण से जुड़ी पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी सेवाओं और अन्य सहायक गतिविधियों को भी इससे गति मिलने की संभावना है। इससे नवा रायपुर में एक व्यापक औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में भविष्य की अर्थव्यवस्था की तैयारी

दुनिया तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ का इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कदम बढ़ाना राज्य की औद्योगिक दूरदर्शिता को दर्शाता है। नवा रायपुर में यश फैब्स द्वारा 110 करोड़ रुपए के निवेश से होम अप्लायंसेज निर्माण इकाई शुरू की गई है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों का संकेत है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर को भारत सरकार की मंजूरी मिलना भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस केंद्र में PCB प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग और EMC टेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे स्थानीय उद्यमियों, स्टार्टअप और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को तकनीकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग आधारित SEZ को मंजूरी मिलना भी प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की दृष्टि से अहम है। पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 5G और 6G तकनीक के लिए GaN आधारित सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन की योजना छत्तीसगढ़ को उच्च तकनीक वाले विनिर्माण क्षेत्र से जोड़ने वाली पहल है।

AI और डेटा सेंटर से डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा

औद्योगिक विकास के साथ साय सरकार का फोकस डिजिटल अधोसंरचना पर भी है। नवा रायपुर में AI आधारित डेटा सेंटर पार्क का विकास इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सेक्टर-22 में CBD रेलवे स्टेशन के समीप करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। लगभग 13.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस पार्क का एक हिस्सा SEZ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा CtrlS द्वारा भी नवा रायपुर में डेटा सेंटर स्थापित करने की तैयारी है। डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं का विस्तार आने वाले वर्षों में रोजगार के नए क्षेत्र तैयार करेगा। इससे नवा रायपुर को पारंपरिक उद्योगों के साथ नई डिजिटल अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने की संभावनाएं मजबूत होंगी।

विकास की रीढ़ बनाने की दिशा में प्रयास

औद्योगिक विकास का वास्तविक लाभ तभी व्यापक स्तर पर पहुंचता है, जब बड़े उद्योगों के साथ छोटे और मध्यम उद्यम भी मजबूत हों। साय सरकार ने इसी दृष्टिकोण के साथ एमएसएमईक्षेत्र को भी औद्योगिक विकास की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। नवा रायपुर के सेक्टर-05 में विनिर्माण उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है। यहां वर्तमान में एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है और भविष्य में 12 हजार से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। एमएसएमईके विस्तार से स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े उद्योगों के लिए सहायक औद्योगिक नेटवर्क तैयार होगा। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन, आपूर्ति, सेवा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

निवेश के साथ लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी पर भी जोर

उद्योगों की सफलता केवल भूमि और निवेश पर निर्भर नहीं करती। मजबूत परिवहन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नवा रायपुर में CBD रेलवे स्टेशन का संचालन और सेक्टर-1 तथा सेक्टर-40 में प्रस्तावित आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब इसी व्यापक औद्योगिक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। बेहतर लॉजिस्टिक्स से कच्चे माल की आपूर्ति, तैयार उत्पादों के परिवहन और बाजारों तक पहुंच आसान होगी। इससे उद्योगों की लागत और समय दोनों को कम करने में सहायता मिलेगी।

राजधानी की पहचान से आगे रोजगारधानी की ओर

नवा रायपुर की बदलती तस्वीर साय सरकार की उस विकास सोच को रेखांकित करती है, जिसमें आधुनिक अधोसंरचना को औद्योगिक निवेश और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। एक ओर यहां प्रशासनिक राजधानी की सुविधाएं विकसित हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और एमएसएमईजैसे विविध क्षेत्रों में निवेश का आधार तैयार हो रहा है। इस औद्योगिक विविधता का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नए क्षेत्रों से मजबूती मिलेगी। युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतर रोजगार और कौशल आधारित अवसर मिल सकेंगे। स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में निवेश का वातावरण और मजबूत होगा।

निवेश से विकास और विकास से रोजगार का नया चक्र

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को लेकर तैयार की जा रही नई तस्वीर यह संकेत देती है कि प्रदेश अब केवल परंपरागत संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहना चाहता। सरकार की प्राथमिकता ऐसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की है, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था के आधार बनेंगे। टेक्सटाइल पार्क में लगभग 10 हजार रोजगार की संभावना, फार्मा पार्क में करीब 1,400 रोजगार, एमएसएमईक्षेत्र में भविष्य में 12 हजार से अधिक रोजगार की संभावना और आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर तथा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बढ़ते निवेश- ये सभी प्रयास मिलकर नवा रायपुर को आर्थिक गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

उद्योगपतियों ने किया छत्तीसगढ़ के जंगलों का विनाश

(पेज 1 का शेष)

विशेष रूप से हसदेव अरण्य, कोरबा और सरगुजा क्षेत्र वन विनाश के प्रमुख उदाहरण बनकर उभरे हैं। वेदांता और अडानी समूह राज्य के जंगलों का विनाश करने का बीड़ा उठाया है। विकास परियोजनाओं के नाम पर पर्यावरण के विनाश का खुला खेल चल रहा है। छत्तीसगढ़ के जंगल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवनरेखा हैं। औद्योगिक विकास और खनिज दोहन ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दी है, लेकिन इसके साथ वन विनाश, विस्थापन और पर्यावरणीय संकट भी बढ़े हैं।

खनन और औद्योगिक विस्तार के नाम पर आदिवासियों की आजीविका पर प्रहार

छत्तीसगढ़ में कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता के कारण बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। कोरबा को देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, जहाँ विशाल कोयला खदानें और ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं। इसी प्रकार रायगढ़, सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में भी अनेक खनन परियोजनाएँ संचालित हो रही हैं। खनन परियोजनाओं के लिए सबसे पहले वन भूमि को गैर-वन उपयोग के लिए परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई होती है। कई बार खुली खदान पद्धति अपनाई जाती है, जिससे विशाल भूभाग पूरी तरह उजड़ जाता है। CAG की रिपोर्टों में भी अवैध खनन और खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। लेकिन प्रदेश

सरकार में बैठे विभागीय मंत्री और आला अफसर चंद प्रलोभन के कारण जंगलों को नष्ट करने की अनुमति दे रहे हैं।

हसदेव अरण्यः संघर्ष का प्रतीक

छत्तीसगढ़ के वन विनाश की चर्चा हसदेव अरण्य के बिना अधूरी है। हसदेव अरण्य मध्य भारत के सबसे बड़े सतत वन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। हाल के वर्षों में यहाँ कई कोयला खनन परियोजनाओं को अनुमति दी गई। केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक जैसी परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद स्थानीय समुदायों और पर्यावरणविदों ने विरोध दर्ज कराया। हसदेव अरण्य का मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच चल रहे संघर्ष का प्रतीक बन गया है। एक ओर सरकार और उद्योग क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक विकास की आवश्यकता बताते हैं, जबकि दूसरी ओर स्थानीय समुदाय जंगलों और आजीविका की रक्षा की मांग करते हैं। 1,742.6 हेक्टेयर वन भूमि और लगभग 4.48 लाख वृक्ष खनन परियोजना के लिए प्रभावित होने वाले हैं। पीईकेबी यानि पारसा ईस्ट और कांटा बासन, यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख कोयला खनन परियोजना है। इस खदान का मुख्य काम राजस्थान को बिजली बनाने के लिए कोयला निकालना है। परियोजना में लगभग 96,000 पेड़ काटे गए हैं।

वेदांता समूह की सक्ति परियोजना

वेदांता समूह मुख्यतः खनन, धातु और ऊर्जा क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है। वेदांता की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना सक्ति का 1,200 MW ताप विद्युत संयंत्र है, जिसके लिए लगभग 2,114 एकड़ भूमि उपयोग में लाई गई है। कंपनी के पास आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ होने का दावा है, लेकिन कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन के कारण पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर बहस जारी है। 2026 की औद्योगिक दुर्घटना ने सुरक्षा मानकों और नियामकीय निगरानी पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। अप्रैल 2026 में सक्ती संयंत्र में विस्फोट हुआ जिसमें कम से कम 17 लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा तमनार और गेवरा कोयला खदानें (रायगढ़-कोरबा), लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एनटीपीसी) जैसी परियोजनाएं हैं जो सीधे तौर पर पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं।

सच्चा विकास वही होगा जो प्रकृति, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करे। यदि जंगलों का अंधाधुंध दोहन जारी रहा तो भविष्य की पीढ़ियाँ एक समृद्ध प्राकृतिक धरोहर से वंचित हो जाएँगी। इसलिए छत्तीसगढ़ के जंगलों की रक्षा केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अस्तित्व और सतत विकास का भी प्रश्न है।

सम्पादकीय

रांची के युवाओं का सवाल परीक्षा से आगे भरोसे की लड़ाई

रांची की सड़कों पर इन दिनों जो युवा दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों में केवल तख्तियां नहीं हैं, उनकी आंखों में अपने भविष्य का सवाल है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से उठती आवाजें केवल किसी एक परीक्षा के परिणाम या किसी एक भर्ती प्रक्रिया की शिकायत नहीं हैं, बल्कि उस बेचैनी की अभिव्यक्ति हैं जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के भीतर आकार ले रही है। JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लंबा खिंच चुका है और अब यह झारखंड की राजनीति तथा प्रशासन के सामने एक गंभीर प्रश्न बनकर खड़ा है- क्या राज्य अपने युवाओं के सपनों के साथ न्याय कर पा रहा है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तो वह केवल किताबें नहीं पढ़ता। वह अपने जीवन के कई वर्ष दांव पर लगाता है। परिवार की आर्थिक क्षमता, माता-पिता की उम्मीदें, व्यक्तिगत आकांक्षाएं और भविष्य की योजनाएं- सब कुछ एक परीक्षा से जुड़ जाता है। ऐसे में यदि प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षा में अनियमितता या भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है तो नुकसान केवल एक अभ्यर्थी का नहीं होता, बल्कि पूरी व्यवस्था में उसके विश्वास को चोट पहुंचती है। रांची का आंदोलन इसी भरोसे की पुनर्स्थापना की मांग है।

छात्र संगठनों ने परीक्षा रद्द करने, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार जैसी मांगें उठाई हैं। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के दौर भी हुए, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस समाधान सामने न आने के कारण आंदोलन जारी रहा। 10 अगस्त को विधानसभा की ओर मार्च के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद आंदोलन की मूल चिंता वहीं रही। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही। लोकतंत्र में सरकार और आंदोलनकारी के बीच संवाद की भूमिका यहीं से शुरू होती है। सरकार के लिए हर विरोध को राजनीतिक चश्मे से देखना जितना उचित नहीं है, उतना ही आंदोलनकारियों के लिए भी हर प्रशासनिक निर्णय को पूर्वाग्रह से देखना समाधान का रास्ता नहीं हो सकता। सरकार और युवाओं के बीच टकराव की स्थिति जितनी लंबी होगी, उतना ही अविश्वास गहरा होगा।

रांची का आंदोलन हमें दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए हालिया युवा आंदोलनों की भी याद दिलाता है। दोनों जगह युवाओं ने परीक्षा और रोजगार की व्यवस्था में विश्वास तथा जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए, लेकिन दोनों आंदोलनों की परिस्थितियां और संगठनात्मक स्वरूप अलग हैं। रांची का आंदोलन मुख्यतः झारखंड की भर्ती परीक्षाओं, JPSC-JSSC की प्रक्रियाओं और राज्य में सरकारी नौकरियों की व्यवस्था से जुड़ा है। हालिया घटनाक्रम में झारखंड सरकार द्वारा 22 भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करने तथा 17 अन्य परीक्षाओं की CID जांच के आदेश की खबर सामने आई है। यह निर्णय पारदर्शिता की दिशा में कदम हो सकता है, लेकिन इसके साथ एक दूसरी चुनौती भी पैदा हुई है। पहले से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता। इसलिए सुधार की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोषियों पर कार्रवाई के साथ निर्दोष अभ्यर्थियों के हितों की भी रक्षा हो। यही वह बिंदु है जहां सरकार की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता की असली परीक्षा होती है। जरूरत केवल परीक्षा रद्द करने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र की सुरक्षा से लेकर परिणाम जारी होने तक प्रत्येक चरण तकनीकी रूप से सुरक्षित, प्रशासनिक रूप से पारदर्शी और कानूनी रूप से उत्तरदायी हो। भर्ती आयोगों की कार्यप्रणाली को मजबूत करना, समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर जारी करना, शिकायतों के लिए स्वतंत्र तंत्र बनाना और जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करना जैसे कदम युवाओं के भरोसे को मजबूत कर सकते हैं।

इसके साथ ही आंदोलन का चरित्र भी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार उतना ही पवित्र है जितना कानून का शासन। छात्रों को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहे, यह जिम्मेदारी भी उनकी है।

सियासी गहमागहमी

किसे मिलेगी मप्र भाजपा में मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी?

मध्यप्रदेश भाजपा में मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज है। संगठन के स्तर पर यह पद महज एक नियुक्ति नहीं, बल्कि सरकार और संगठन की नीतियों, उपलब्धियों तथा राजनीतिक संदेश को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। ऐसे में पार्टी की नजर ऐसे चेहरे पर होगी, जो संगठन की विचारधारा और नेतृत्व की प्राथमिकताओं को समझने के साथ ही मीडिया के बदलते स्वरूप और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बारीकियों से भी भलीभांति परिचित हो। संभावित नामों को लेकर अटकलें स्वाभाविक हैं, लेकिन अंतिम निर्णय संगठन की जरूरत, अनुभव और नेतृत्व के विश्वास के आधार पर ही होने की संभावना है। नए मीडिया प्रभारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सवालों का तथ्यात्मक और प्रभावी जवाब देने के साथ सरकार की योजनाओं को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाने की होगी। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संवाद की रणनीति भी पारंपरिक मीडिया से कहीं आगे बढ़ानी होगी। फिलहाल सवाल यही है मध्यप्रदेश भाजपा में मीडिया की कमान किस अनुभवी और प्रभावशाली चेहरे को सौंपी जाएगी?

किसानों की स्थिति को देख पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं दुखी

मध्यप्रदेश में किसानों की स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की चिंता एक बार फिर राजनीतिक विमर्श का विषय बनी है। खेती-किसानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन की आधारशिला है, ऐसे में किसानों की आय, फसल का उचित मूल्य, समय पर खाद-बीज की उपलब्धता और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान जैसे मुद्दे सीधे लाखों परिवारों के जीवन से जुड़े हैं। कमलनाथ लगातार किसान हितों को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं और उनका कहना है कि घोषणाओं से आगे बढ़कर किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान जरूरी है। हालांकि किसान कल्याण को लेकर सरकार की ओर से भी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों की अपेक्षाओं और सरकारी व्यवस्था के बीच यदि कोई अंतर दिखाई देता है तो उसे दूर करना शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। किसान को राहत केवल तत्काल सहायता से नहीं, बल्कि मजबूत बाजार व्यवस्था, सिंचाई, आधुनिक कृषि तकनीक और स्थिर आय के अवसरों से मिलेगी। सवाल यही है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान कब होगा?

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

देश के हर दलित व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक, हर जगह, हर कदम अपमान किया जाता है। उनकी जितनी बुलंद आवाज होती है, उनपर उतना तेज हमला होता है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी के साथ हल्द्वानी में जो भी हुआ वो "शुद्धिकरण" का नाम दे कर उनके खिलाफ छुआछूत है - और छुआछूत भारत के संविधान के अनुसार दंडनीय अपराध है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

लोकपर्व कजलियाँ -भुजरिया उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ।
यह पर्व अच्छी वर्षा, अच्छी फसल और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है।
यह प्रेम, सौहार्द, सुरक्षा और अपनेपन का एहसास दिलाने वाला पर्व है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

प्रणब मुखर्जी: भारतीय राजनीति के कुशल शिल्पी और विलक्षण राजनेता

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति के विस्तृत आकाश में कुछ व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं, जिन्होंने सत्ता के शिखर पर रहते हुए भी अपनी पहचान पद से अधिक अपने ज्ञान, अनुभव, संसदीय कौशल और राजनीतिक सूझबूझ से बनाई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ऐसे ही विलक्षण राजनेता थे। लगभग पांच दशकों तक भारतीय राजनीति, संसद और शासन-व्यवस्था में सक्रिय रहकर उन्होंने देश की सार्वजनिक जीवन-परंपरा पर अमिट छाप छोड़ी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ-साथ एक कुशल प्रशासक, प्रखर वक्ता, गंभीर अध्येता और सर्वदलीय संवाद एवं सहमति के समर्थक राजनेता के रूप में सदैव स्मरण किए जाते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस के सक्रिय नेता थे तथा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ऐसे राष्ट्रवादी और राजनीतिक परिवेश में पले-बढ़े प्रणब मुखर्जी के व्यक्तित्व में देशसेवा, अनुशासन और सार्वजनिक जीवन के संस्कार प्रारंभ से ही विकसित हुए।

उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास एवं राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की तथा विधि की शिक्षा भी हासिल की। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश से पहले उन्होंने महाविद्यालय में अध्यापन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया। अध्ययन और लेखन के प्रति उनकी गहरी रुचि जीवनपर्यंत बनी रही। वर्ष 1969 में वे पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और यहीं से उनका राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन निर्णायक रूप से प्रारंभ हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मार्गदर्शन में उनकी राजनीतिक प्रतिभा को व्यापक अवसर मिला। 1970 के दशक में उन्होंने केंद्र सरकार में विभिन्न दायित्व संभाले और वर्ष 1982 में पहली बार भारत के वित्त मंत्री बने। वे 1980 से 1985 तक राज्यसभा में सदन के नेता भी रहे। आगे चलकर उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा वाणिज्य, विदेश, रक्षा और वित्त जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2004 से 2012 तक वे लोकसभा के नेता रहे और 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण दायित्व निभाया।

प्रणब मुखर्जी की विशेषता यह थी कि वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि शासन-व्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले संसदीय विद्वान थे। संसद की प्रक्रियाओं, आर्थिक मामलों, विदेश नीति और प्रशासनिक विषयों पर उनकी पकड़ असाधारण मानी जाती थी। अनेक जटिल राष्ट्रीय मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संवाद और सहमति बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2004 से 2012 के बीच उन्होंने अनेक मंत्रिसमूहों की अध्यक्षता करते हुए प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, रोजगार, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर निर्णय प्रक्रिया में योगदान दिया।

अर्थव्यवस्था और संस्थागत निर्माण के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक तथा नाबार्ड जैसे संस्थानों के निर्माण की प्रक्रिया में उनका योगदान रहा। केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे से संबंधित 1991 में विकसित सूत्र को 'गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूला' के नाम से जाना गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भूमिका निभाई। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और शिक्षा के महत्व पर विशेष बल दिया। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल उनके दीर्घ राजनीतिक अनुभव और संवैधानिक दृष्टि का परिचायक रहा।

साहित्य और अध्ययन से उनका गहरा लगाव था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र-निर्माण से जुड़े विषयों पर कई पुस्तकें लिखीं। उनकी विद्वत्ता और सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए। वर्ष 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, वर्ष 2008 में पद्म विभूषण और वर्ष 2011 में भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रशासक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया। 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। उनके निधन के साथ भारतीय राजनीति ने एक ऐसे अनुभवी राजनेता को खो दिया, जिसकी पहचान दलगत सीमाओं से परे एक गंभीर संसदीय व्यक्तित्व के रूप में थी। प्रणब मुखर्जी का जीवन यह संदेश देता है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि अध्ययन, संवाद, संवैधानिक मर्यादा और राष्ट्रसेवा का दायित्व भी है। गांव की मिट्टी से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाली उनकी यात्रा भारतीय लोकतंत्र की संभावनाओं और शक्ति का प्रेरक उदाहरण है। उनका ज्ञान, अनुभव, संसदीय परंपराओं के प्रति सम्मान और राष्ट्रहित में सहमति बनाने की क्षमता आने वाली पीढ़ियों के लिए लंबे समय तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।

प्रदेश की करीब 5 लाख महिलाएं 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर बढ़ा रहीं आत्मनिर्भरता की ओर कदम

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देहरादून में आयोजित दो कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर प्रदेश की मातृशक्ति के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम जीएमएस रोड स्थित चौधरी फार्म में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में प्रतिभाग किया। इसके पश्चात उन्होंने हाथीबड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। दोनों ही कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रक्षा सूत्र बांधा और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्नेह और आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उत्तराखंड की समस्त माताओं और बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह पवित्र पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की नई सौगात लेकर आए। उन्होंने कहा कि आज बहनों के बीच पहुंचकर उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे कोई भाई अपने घर-परिवार के बीच पहुंचा हो। मातृशक्ति से मिल रहा स्नेह और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उन्हें उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक की सेवा के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का पर्व नहीं है, बल्कि यह अटूट स्नेह, विश्वास, समर्पण और सुरक्षा के उस पवित्र संकल्प का पर्व है, जिसे भाई अपनी बहन के प्रति जीवन भर निभाने का प्रयास करता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि रिश्ते केवल अधिकारों से नहीं, बल्कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन से मजबूत होते हैं। भाई का बहन के प्रति स्नेह एवं सुरक्षा का संकल्प और बहन का भाई के प्रति अटूट विश्वास- इन दोनों पवित्र भावनाओं को रक्षाबंधन और अधिक मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन हमें नारी सम्मान के महत्व का भी स्मरण कराता है। नारी का सम्मान केवल हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और संस्कार का आधार है। नारी परिवार की आधारशिला होने के साथ-साथ समाज और संस्कृति की भी मूल शक्ति है। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है, वही समाज वास्तव में समृद्ध और संस्कारित बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मातृशक्ति होती है। जब महिला सशक्त होती है तो उसका लाभ केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता है। आज महिलाएं अंतरिक्ष से लेकर देश की सीमाओं तक, घर-परिवार से लेकर उद्योग और व्यवसाय तक हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। अब महिलाएं केवल सहभागिता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नेतृत्व की भूमिका में भी आगे बढ़ रही हैं।

महतारी वंदन योजना से रक्षाबंधन से पहले खुशियां हुईं दोगुनी

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का पर्व है। इस पावन अवसर पर जब परिवार के बीच खुशियां बांटने की तैयारी हो, तब समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता इन खुशियों को और भी खास बना देती है। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम हर्रा निवासी दीपलक्ष्मी राय के लिए इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व कुछ ऐसी ही खुशियां लेकर आया है। महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि रक्षाबंधन से पहले उनके बैंक खाते में पहुंची, जिससे उनके परिवार में त्योहार को लेकर उत्साह और खुशी का माहौल है।

राखी की खुशियों में आर्थिक संबल का रंग

दीपलक्ष्मी के लिए महतारी वंदन योजना की राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि जरूरत के समय मिलने वाला भरोसे का सहारा है। उनका कहना है कि नियमित रूप से मिलने वाली सहायता राशि से महिलाओं को अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में सुविधा होती है। परिवार की आवश्यकताओं में आर्थिक योगदान देने का अवसर मिलने से महिलाओं के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि त्योहारों के समय घर की जरूरतें सामान्य दिनों की अपेक्षा बढ़ जाती हैं। ऐसे में योजना की राशि से जरूरी सामान की खरीदारी करने में मदद मिलती है। रक्षाबंधन से पहले राशि मिलने से इस बार वे अपने परिवार के साथ पर्व को लेकर अधिक उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिलना उनके लिए उपयोगी है। इससे वे अपनी जरूरतों के लिए परिवार पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय स्वयं भी निर्णय ले सकती हैं और आवश्यक खर्चों में योगदान कर सकती हैं।

IITTM ग्वालियर में प्रो. प्रशांत गौतम ने निदेशक का पदभार संभाला

-संतोष कुमार कुशवाह

जगत प्रवाह. ग्वालियर। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (IITTM), ग्वालियर में प्रो. (डॉ.) प्रशांत गौतम ने निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण से पूर्व उन्होंने परिसर में भगवान गणपति एवं मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की। इसके बाद ऑडिटोरियम में स्वागत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कामाक्षी महेश्वरी ने किया, स्वागत उद्बोधन नोडल अधिकारी प्रो. सौरभ दीक्षित ने दिया। छात्रों द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया और आभार डॉ. चंद्र शेखर बरुआ ने व्यक्त किया। प्रो. गौतम पर्यटन प्रबंधन के प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हैं। वे पंजाब युनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में प्रोफेसर रह चुके हैं और पूर्व में IITTM ग्वालियर में Lecturer के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पर्यटन में पीएच.डी. की है। संस्थान परिवार ने उनके नेतृत्व में नई ऊंचाइयों की उम्मीद जताई है।

एथनाल पेट्रोल ने चीनी का बढ़ाया संकट

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

भारतीय बाजार में गन्ने से एथनाल के निर्माण ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इस गंभीर समस्या ने जहां चीनी को उम्मीद से ज्यादा महंगा कर दिया है, वहीं चीनी आयात करने की स्थिति भी पैदा हो गई है। केंद्र सरकार ने 10 साल में पहली बार चीनी आयात करने का फैसला लिया है। चीनी अब डॉलर देकर विदेश से मंगाई जाएगी। जबकि 2022 तक ईयू और यूएस को तय कोटा निर्यात के बाद यह प्रतिबंध लगाना पड़ता था कि अब और चीनी निर्यात नहीं की जाए। जिससे घरेलू मांग की पूर्ति आसान बनी रहे और चीनी महंगी भी न हो। अब यह स्थिति निर्मित हो गई है कि घर-घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी का भंडार पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत कम हो गया है। इस कमी का प्रमुख कारण गन्ने का उपयोग एथनाल बनाने में किया जाना माना जा रहा है। भारत में अनाज से शराब पूर्व से ही बनाई जा रही है। खाद्य उपज से पेट्रोल और शराब का बड़ी मात्रा में निर्माण नीति नियंताओं की अदूरदर्शिता प्रकट करती है।

बीते दो माह के भीतर ही चीनी की कीमतें उछलकर 40 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। आगे रक्षाबंधन, गणेश महोत्सव और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे बड़े त्यौहार हैं, जिनमें मिठाई और प्रसाद वितरण के लिए शकर की बड़ी मांग बनी रहती है। इसके तत्काल बाद नवदुर्गा, विजयादशमी और दीपावली जैसे बड़े पर्व हैं, जिनमें चीनी की सर्वाधिक खपत होती है। अतएव समय पर चीनी आयात नहीं हो पाती है तो चीनी के दाम आसमान छूने लग जाएंगे। हालांकि सरकार यह जता रही है कि पेट्रोल में एथनाल की मात्रा बढ़ाने से चीनी महंगी नहीं हुई है, बल्कि खराब मौसम के चलते गन्ने की फसल की कम पैदावार के कारण देष में चीनी का उत्पादन कम हुआ है। सरकार एक अन्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के दामों में वृद्धि बता रही हैं। बावजूद सरकार ई-20 एथनाल पेट्रोल के उत्पादन पर अंकुश लगाने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि सरकार ने ई-10 यानी 10 फीसदी एथनाल मिश्रित पेट्रोल बनाने के सुझावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

दरअसल देश में एथनाल उत्पादन की क्षमता तेजी से बढ़कर 2000 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष से ज्यादा हो गई है। एथनाल का यह उत्पादन 478 महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लगे संयंत्रों में किया जा रहा है। जबकि पेट्रोल वाहनों में एथनाल मिला पेट्रोल उपयोग करने से वाहन खराब हो रहे हैं। इस कारण मौजूदा मांग उत्पादन से कम बनी हुई है। बावजूद उदयोगपति एथनाल निर्माण के नए संयंत्रों के निर्माण में लगे हैं। इस सेक्टर को बैंकों ने एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। अब सरकार की दुविधा यह है कि यदि पेट्रोल में ब्लेंडिंग घटाई गई तो हजारों करोड़ के बैंक ऋण और देसी-विदेशी निवेश डूबने का संकट बढ़ जाएगा। ब्लेंडिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसके तहत एक तय मात्रा में बायो फ्यूल, यानी ई-20 या ई-10 प्रतिशत पेट्रोल में एथनाल मिलाया जाता है। हालांकि यह जीवाश्म ईंधन जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल है। इस जैव ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा माना जाता है। इस कारण दुनिया के देश जैव ईंधन का उत्पादन बढ़ाने में लगे हैं।

केअर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अंत तक एथनाल उत्पादन क्षमता 400 करोड़ लीटर और बढ़ जाएगी। अर्थात कुल उत्पादन क्षमता करीब 2400 करोड़ लीटर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। जबकि 2014 में एथनोल का उत्पादन 421 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष होता था। जो अब चार गुना अधिक हो गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए ई-20 पेट्रोल के लिए 1200 करोड़ लीटर एथनाल की जरूरत पड़ेगी। यही नहीं उद्योगों, फार्मा कंपनियों और रसायन क्षेत्रों में भी अधिकतम 350 लीटर एथनाल की मांग बनी हुई है। 2025 से देशभर में ई-20 पेट्रोल की बिक्री हो रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका-ईरान, रूस-यूक्रेन और इजरायल के युद्धों के चलते केंद्र सरकार ने मजबूरी में अप्रैल-2026 से एथनाल मिश्रित पेट्रोल बाजार में देने की शुरुआत की है। इधर एथनाल के नए संयंत्र लगाए जाने के कारण उद्योग जगत की मांग है कि ई-30 या उससे अधिक एथनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री देशभर में शुरू की जाए। फिलहाल देश में गन्ना, मक्का और अन्य अनाजों से बने एथनाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए। क्योंकि यदि खाद्य सामग्री से बना एथनाल निर्यात होने लग जाएगा तो देश में खाने वाला अनाज की आपूर्ति में तो आएगी ही, उम्मीद से ज्यादा अनाज महंगा भी हो जाएगा। हालांकि वर्तमान में कृषि अवशेष और बायोमास से निर्मित एथनाल के निर्यात की अनुमति सितंबर 2025 से दे दी गई है। किंतु उद्योग जगत अपना फायदा देखते हुए मांग कर रहा है कि सरकार नेपाल और इंडोनेशिया देशों में निर्यात की संभावनाएं तलाशे? अनाज, फल और सब्जी आदमी के जिंदा रहने की बुनियादी शर्त हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली के लिए जरूरी बना दिए गए औद्योगिक उत्पादन और भोग-विलास के उपकरणों को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक स्रोतों में फसलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल दुनिया में हो रहा है। खाद्य संकट बनाए रखने के कारणों में यह एक प्रमुख कारण है। यदि जैविक ईंधन के लिए अनाज के प्रयोग को खुली छूट दे दी जाती है तो भारत में भूख का संकट गहराना तय है। वैसे भी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। यह स्थिति भूख की गंभीर स्थिति दर्शाती है। ऐसे में वाहनों के उत्पादन को बढ़ाना और बैंकों के कर्ज के जरिए उनकी बिक्री आसान करना भूख की स्थिति को और गंभीर बनाएगी।

इस सिलसिले में ब्रिटेन की स्वयंसेवी संस्था ऑक्सफेम ने दुनिया में बढ़ रहे खाद्यान्न संकट के सिलसिले में चेतावनी दी है कि यदि अनाज से शराब और एथनॉल बनाना बंद नहीं किया तो 2030 तक खाद्यान्न की मांग 70 फीसदी तक बढ़ सकती है और अनाज की कीमतें भी दुगनी हो सकती हैं? बावजूद देश की गरीब व लाचार आबादी की चिंता की बजाय भारत सरकार वाहनों के लिए एथनाल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, तो यह चिंता का विषय है।

महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों की आड़ में पति चला रहे अवैध कारोबार?

-बद्री प्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। क्षेत्र में चर्चा है कि कुछ महिला पंच, सरपंच और जनपद सदस्य निर्वाचित होने के बाद उनके स्थान पर उनके पति स्वयं प्रतिनिधि की भूमिका निभा रहे हैं और पद से जुड़े प्रभाव का इस्तेमाल अपने हित में कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कुछ ऐसे मामलों में महिला जनप्रतिनिधियों के पति जुआ, सट्टा गांजा और अवैध शराब जैसे अवैध कारोबार से कथित रूप से जुड़े होने के आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप यह भी हैं कि जनप्रतिनिधि पद से मिलने वाले राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव की आड़ में इन गतिविधियों को संरक्षण देने का प्रयास किया जाता है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या महिला जनप्रतिनिधि को मिले संवैधानिक अधिकार और दायित्वों का इस्तेमाल उनके पति या अन्य परिजन कर सकते हैं? यदि किसी पद की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि कुछ प्रभावशाली लोग अपने जनप्रतिनिधि पद के कारण पुलिस और प्रशासन पर दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है। मामला केवल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधित्व की गरिमा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधि के अधिकारों के वास्तविक उपयोग से जुड़ा है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि शिकायतों और सामने आ रही सूचनाओं की निष्पक्ष जांच कराए। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हो और यदि आरोप निराधार हैं तो तथ्य भी सार्वजनिक किए जाएं।

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

फरक्का जल संधि पर नई सोच की जरूरत

फरक्का समझौते को लेकर बहस कई दशकों से चल रही है। इस समझौते का उद्देश्य गंगा के जल-प्रवाह को नियंत्रित करना था, लेकिन समय के साथ इसके असर ने यह स्पष्ट किया कि नदी-प्रबंधन केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रश्न भी है। भारत के पूर्वी हिस्सों में बाढ़, जलभराव, कटाव और कृषि संकट जैसी समस्याएँ लगातार उठती रही हैं।

फरक्का बांध समझौता (1975) का मकसद गंगा के बहाव को सुव्यवस्थित कर नेपाल और बांग्लादेश के जलवितरण पर प्रभाव कम करना था, पर इसके दुष्प्रभाव खासकर भारत के पूर्वी भागों में लंबे समय तक महसूस किए गए। सबसे बड़ा नुकसान बाढ़ और जलभराव के स्वरूप में दिखा। बांध ने गंगा की पारंपरिक घुमावदार को बदलकर कुछ क्षेत्रों में तलछट जमा कर दिया, जिससे नदी चैनल ऊंचे हुए और बरसात में पानी आस-पास के गांवों व कृषि भूमि में फंसने लगा। परिणामस्वरूप फसल हानि और जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हुई है। नदी तलछट व कटाव के कारण तंत्र में बदलाव ने कई ग्रामीण समुदायों को विस्थापित किया। मछली पकड़ने पर निर्भर समुदायों की आजीविका प्रभावित हुई क्योंकि नदी पारिस्थितिकी में परिवर्तन से मछली संसाधन कम हुए। साथ ही, जल संचयन और निकास में असंतुलन से सैकड़ों उपयोगकर्ता जैसे किसान, मत्स्यपालक जल संकट और बाढ़ दोनों ही झेलते रहे।

नीति निर्माण की कमी भी दोषी रही है । सितंबर 1996 में तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा प्रतिपादित "गुजराल डॉक्ट्रिन" का मूल मंत्र था कि भारत को बड़ा दिल दिखाते हुए पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में एकतरफा रियायत देनी चाहिए। विडंबना यह रही कि इस नीति के तहत दिसंबर 1996 में बंगला देश को जल अधिकार सौंपते वक्त जब बिहार की हितों की बलि चढ़ाई जा रही थी, तब मुख्यमंत्री लालू यादव मौन साधे रहे जो उस वक्त के संजुक्त मोर्चा के एक प्रभावी नेता थे। इस समझौते से बिहार राज्य बहुत पीड़ित रहा। बिहार को इससे बाढ़ और सुखाड़ की दोहरी मार झेलनी पड़ी।

क्षेत्रीय साझेदारी और सतत् नदी प्रबंधन के लिए निरंतर डेटा-साझा व्यवस्था व बहु-स्तरीय निगरानी नहीं बन पाई। समाधान के तौर पर अनुकूलित बहस चाहिए। नदी पुनर्संरचना (river restoration), तलछट प्रबंधन, पारिस्थितिक प्रवाह सुनिश्चित करना, और स्थानीय समुदायों को शामिल कर पुनर्वास योजनाएँ लागू करना। साथ ही, पड़ोसी देशों के साथ पारदर्शी जल-शेयरिंग वार्ता में वैज्ञानिक डेटा आधारित निर्णय जरूरी हैं। अब जबकि फरक्का जल संधि को 30 वर्षों की समय सीमा दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रहा है, तब यह प्रश्न केवल कूटनीतिक नहीं , बल्कि व्यापक जनहित और जल सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रहित से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। फरक्का समझौते ने भौगोलिक और आर्थिक स्तर पर कुछ फायदे दिए, पर उन नुकसानों का सामना करने के लिए सक्रिय, सामुदायिक-केंद्रित और पारस्परिक रूप से सहमति-आधारित नीतियाँ आज भी अनिवार्य हैं। फरक्का बैराज और फरक्का जल संधि को अपनी जगह उपयोगिताएं हो सकती है, लेकिन इसके लिए गंगा बेसिन पर निर्भर राज्यों, खासकर बिहार के व्यापक हितों की अनदेखी अब और नहीं की जा सकती। अब समय है कि भारत नीति-स्तर पर अधिक व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए।

पड़ोसी देशों से संवाद को टकराव नहीं, सहयोग की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। जल-साझेदारी पर पारदर्शी डेटा, समय पर सूचना और आपसी भरोसा ही स्थायी समाधान दे सकता है। फरक्का विवाद से सबक लेकर भारत को ऐसी जल-नीति बनानी चाहिए जो विकास, पर्यावरण और जनजीवन तीनों के बीच संतुलन स्थापित करे।

जन आंदोलनः सड़क पर उठे सवाल कैसे बदल देते हैं सत्ता की सियासत

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

भारतीय राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है। अचानक युवा केवल भाषणों में देश का भविष्य नहीं रहा, वह राजनीतिक दलों के वर्तमान एजेंडे की प्राथमिकता बन गया है। सरकार कैंपस तक पहुँचने की रणनीति बना रही है, मंत्री विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद करेंगे, सोशल मीडिया की भाषा और अंदाज बदल रहा है, राज्यों में Gen-Z से सीधे जुड़ने के कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं। विपक्ष भी शिक्षा, परीक्षा, रोजगार और युवा आकांक्षाओं को अपनी राजनीतिक रणनीति के केंद्र में ला रहा है। सवाल है- आखिर ऐसा अचानक क्यों? इसका एक बड़ा जवाब कुछ सप्ताह पीछे दिल्ली के जंतर-मंतर पर मिलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की गड़बड़ियों, पेपर लीक, रोजगार और जवाबदेही के सवालों पर खड़े हुए Gen-Z आंदोलन ने भले अपना धरना समाप्त कर दिया हो, लेकिन जाते-जाते उसने राजनीतिक दलों के सामने एक नया चुनावी सच रख दिया- इस पीढ़ी को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं है।

दरअसल भारतीय लोकतंत्र में यह पहली बार नहीं हुआ। यहाँ चुनाव सरकार बदलते हैं, लेकिन कई बार आंदोलन राजनीति की दिशा बदल देते हैं। सड़क पर उठी आवाज संसद तक पहुँचती है और फिर वही मुद्दा राजनीतिक दलों की भाषा, घोषणापत्र और चुनावी रणनीति का हिस्सा बन जाता है। स्वतंत्र भारत का इतिहास ऐसी कई "आग" का साक्षी है। 1965 में तमिलनाडु का हिंदी-विरोधी आंदोलन भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता के प्रश्न पर उभरा। छात्रों की बड़ी भागीदारी वाले इस आंदोलन के बाद 1967 में कांग्रेस का पुराना वर्चस्व टूटा और सी.एन. अन्नादुरै के नेतृत्व में डीएमके सत्ता में आई। आंदोलन ने केवल भाषा की बहस नहीं बदली, दक्षिण भारत की राजनीति का स्थायी समीकरण बदल दिया।

1974 में गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र असंतोष से शुरू हुआ। उसकी चिंगारी बिहार पहुँची और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में "संपूर्ण क्रांति" का विशाल आंदोलन खड़ा हुआ। आपातकाल और उसके बाद बने राजनीतिक वातावरण में 1977 में पहली बार केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। जेपी आंदोलन ने बताया कि युवा किसी आंदोलन की संख्या भर नहीं, सत्ता परिवर्तन की भूमिका भी लिख सकता है।

1979 से 1985 का असम आंदोलन इससे आगे गया। ऑल असम

स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में छह वर्ष चले आंदोलन के बाद असम समझौता हुआ। आंदोलन से निकले नेताओं ने असम गण परिषद बनाई और सत्ता तक पहुँचे। यानी आंदोलन मांग करते-करते स्वयं राजनीतिक विकल्प बन गया।

मंडल और मंदिर ने बदल दिया राजनीति का गणित

फिर आया 1990 का दौर। मंडल आयोग की सिफारिशों और उसके पक्ष-विपक्ष में हुई लामबंदी ने सामाजिक न्याय, OBC प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी को राजनीति के केंद्र में ला दिया। उसी समय राम जन्मभूमि आंदोलन ने सांस्कृतिक-धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी धुरी बनाया। मंडल और मंदिर ने मिलकर उत्तर भारत की राजनीति का पुराना गणित ही बदल दिया।

आंदोलन - दिल्ली की सड़क से केंद्र तक

2011 में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन फिर दिल्ली की सड़कों से राजनीति के केंद्र तक पहुँचा। लोकपाल राष्ट्रीय मुद्दा बना और उसी आंदोलन से आगे चलकर आम आदमी पार्टी जैसी नई राजनीतिक शक्ति निकली। 2012 का निर्भया आंदोलन और अलग था। उसके पीछे न कोई राजनीतिक दल था, न कोई स्थापित नेतृत्व। फिर भी युवाओं और नागरिकों का स्वतःस्फूर्त आक्रोश इतना व्यापक हुआ कि महिला सुरक्षा राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडा बनी और आपराधिक कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। 2020-21 के किसान आंदोलन ने एक बार फिर यही सिद्धांत दोहराया। एक वर्ष से अधिक चले विरोध के बाद केंद्र सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े। संदेश साफ था - लोकतंत्र में बहुमत सरकार को निर्णय लेने की शक्ति देता है, लेकिन जनभावना को हमेशा अनसुना करने का अधिकार नहीं।

ऐतिहासिक युवा आंदोलन

इसी ऐतिहासिक क्रम में अब 2026 का युवा आंदोलन जुड़ गया है। उस आंदोलन की सफलता को केवल इस आधार पर नहीं मापा जाना चाहिए कि कौनसा फैसला हुआ या किस मंत्री ने इस्तीफा दिया। उसका बड़ा राजनीतिक असर अब दिख रहा है, उसने Gen-Z को राजनीतिक दलों की प्राथमिकता बना दिया है। हाल के दिनों में भाजपा और सरकार की युवा-केंद्रित आउटरीच तेज हुई है। केंद्र स्तर पर विश्वविद्यालयों और युवाओं से सीधे संवाद की योजनाएँ सामने आई हैं, जबकि राज्यों में भी Gen-Z तक पहुँचने के विशेष प्रयास हो रहे हैं। कांग्रेस भी शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था जैसे युवा-सरोकारों को प्रमुखता दे रही है। यानी सत्ता और विपक्ष दोनों ने संदेश पढ़ लिया है - युवा असंतोष अब केवल सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं, राजनीतिक शक्ति भी बन सकता है।

एक हाथ में वोटर कार्ड, दूसरे में स्मार्टफोन

यह भारत की पहली विशाल मतदाता पीढ़ी है जिसके एक हाथ में वोटर कार्ड और दूसरे में स्मार्टफोन है। वह नेता का भाषण सुन सकती है और उसी समय उसका फैक्ट-चेक भी कर सकती है। पहले राजनीतिक दल संदेश बनाते थे और कार्यकर्ता उसे जनता तक पहुँचाते थे; आज एक छात्र का वीडियो, एक मीम, एक पॉडकास्ट या तीस सेकंड की रील लाखों लोगों के बीच राजनीतिक विमर्श खड़ा कर सकती है।

युवा अब पूछेगा- नौकरियाँ कहाँ हैं? भर्ती समय पर क्यों नहीं होती? परीक्षा का पेपर सुरक्षित क्यों नहीं है? डिग्री के बाद अवसर क्या है? AI और ऑटोमेशन के दौर में मेरा कौशल कहाँ खड़ा है? स्टार्टअप और स्वरोजगार के लिए वास्तविक व्यवस्था क्या है? आंदोलन खत्म हो जाते हैं। धरने उठ जाते हैं। जंतर-मंतर फिर सामान्य हो जाता है। लेकिन सफल आंदोलन की असली पहचान यही है कि उसके जाने के बाद भी राजनीति पहले जैसी नहीं रहती और शायद इस बार भी वही हो रहा है। भारत की राजनीति युवाओं की तरफ देख रही है - क्योंकि युवा अब केवल वोट देने वाली पीढ़ी नहीं, एजेंडा तय करने वाली पीढ़ी बनने की ओर है।

अब नेतृत्व की बारी है

नारी शक्ति वंदन

की जिम्मेदारी है

समृद्धि | सम्मान | सशक्तीकरण

महतारी वंदन
68 लाख माताओं- बहनों के खातों में अब तक ₹ 19,444 करोड़

महतारी सदन
महिला स्वरोजगार केंद्र के रूप में अब तक 137 महतारी सदनों का निर्माण

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
39.49 लाख से अधिक माताओं- बहनों की रसोई हुई धुंआ मुक्त

R.O. No. : 13992/ 1

रक्षाबंधन का त्योहार
विष्णु भैया का उपहार

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

/ChhattisgarhCMO
/DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)